संस्करण–7

राजीविका

एक नज़र में

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्

राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई– जयपुर

कोविड -19 से राहत में राजीविका ने निभाई अहम भूमिका

कोविड –19 का दुष्प्रभाव हर किसी पर देखा जा सकता है लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर तबका और दिहाड़ी पर निर्भर गरीब मजदूर वर्ग अत्यधिक बदहाल स्थिति में हैं। लॉकडाउन के कारण उनके रोजगार पर संकट है जिससे आर्थिक दशा पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। उनके स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं।

राजस्थान ग्रामीण विकास परिषद (आरजीएवीपी) क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन (सीएलएफ) के सहयोग से ग्रामीण गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है। इसी दिशा में राजीविका ने जिला प्रशासन और विभिन्न ग्राम पंचायतों के समर्थन के साथ कई सकारात्मक पहल की हैं । कोविड –19 के संकट काल में इन पहलों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता मिल रही है। मास्क निमार्ण और वितरण, राशन किटों का वितरण और बीसी सखी (बिजनेस कॉरसपोंडेंट) के माध्यम से वित्तीय लेनदेन सहायता सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, इसके साथ ही जैविक खेती, किचन गार्डन और पोल्ट्री के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं अपने परिवार की आय में योगदान दे रहीं हैं। शुरुआत में मास्क निर्माण के कार्य ग्राम पंचायतों की निगरानी और मार्गदर्शन के साथ किए गए, हालांकि अब विभिन्न जिलों की एसएचजी महिलाएं स्वयं पहल करते हुए मास्क निर्माण के कार्य में लग गई हैं। उनके इस कार्य से मास्क की उपलब्धता सरल हुई है और साथ ही ग्रामीण महिलाओं को आय का साधन भी प्राप्त हुआ है।

इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट (IPPP)

राजसमंद जिले के भीम ब्लॉक में IPPP परियोजना के तहत 200 परिवारों द्वारा 55,25,282 रुपए की बिक्री की गई है। लाभान्वित परिवारों को प्रति चूजा 109 रुपए की आय हुई। बिक्री से हुई कुल 55,25,282 रुपए की आय में से 10,64,773 रुपए की आय लॉकडाउन की अवधि के दौरान हुई। कोविड –19 के कारण हुए लॉकडाउन में गरीब ग्रामीण परिवारों को इससे आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। इस आजीविका गतिविधि की सफलता और सकारात्मक परिणाम को ध्यान में रखते हुए राजीविका ने राजस्थान के एक लाख परिवारों को IPPP परियोजना में शामिल करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है।

मास्क निर्माण एवं वितरण

राजस्थान के सभी 33 जिलों में अब तक एसएचजी महिलाओं ने कुल 12,75,199 मास्क बनाए हैं। 24749 से अधिक एसएचजी महिलाएँ मास्क के उत्पादन में शामिल हुई हैं। जिला प्रशासन और ग्राम पंचायतों की मदद और स्वैच्छिक योगदान के साथ, इन एसएचजी महिलाओं द्वारा मास्क निर्मित किए गए हैं। सूती कपड़े से बने ये मास्क कम लागत के होते हैं और साथ ही प्रभावी भी रहते हैं। 15 रु में कपड़े से बने डबल लेयर मास्क टिकाऊ होते हैं क्योंकि इन्हें धोकर पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है।

खाद्य पदार्थों की सुलभता हुई सुनिश्चित

अब तक 171782 क्विंटल से अधिक अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं राज्य भर के जरूरतमंद लोगों को वितरित की गई हैं। राशन पैकेट बनाने के लिए बड़ी मात्रा में वस्तुओं की खरीद के साथ ही स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त एसएचजी महिलाओं ने घर–घर जाकर कच्चे खाद्य पदार्थों को भी एकत्र किया है और जिला प्रशासन के सहयोग से जरूरतमंदों को घर–घर जाकर वितरित किया है।

एसएचजी महिलाओं को PPE किट के सामान जैसे कैप्स, दस्ताने, जूता कवर आदि बनाने में प्रशिक्षित किया जा रहा है और इनका उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है। जोधपुर और उदयपुर जिले में महिलाओं ने किट की कुछ वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया है।

इसके अतिरिक्त 154 बीसी सखियों (व्यापार संवाददाताओं) ने 3714.04 लाख रुपये के 127235 वित्तीय लेनदेन के साथ एसएचजी महिलाओं को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता की है।

इन सभी गतिविधियों के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों और सुरक्षा मानदंडों का पालन किया जा रहा है जैसे कि मास्क पहनना, हाथ धोना एवं सामाजिक दूरी बनाए रखना आदि।

देसाई फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ राजीविका एसएचजी महिलाएं अब मशीन द्वारा बनाएंगी मास्क

गुजरात की देसाई फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ मिल कर राजीविका एसएचजी महिलाएं मशीन द्वारा मास्क निर्माण करेंगी। देसाई फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा राजीविका को मास्क और पैड बनाने का मशीन प्रदान की गई है। देसाई फाउंडेशन ट्रस्ट राजीविका सीएलएफ को पैकेजिंग मैटेरियल, ब्रांडिंग और प्रचार के लिए भी सहयोग प्रदान करेगी। इस मशीन द्वारा मास्क एवं सैनिटरी पैड बनाने का कार्य किया जाता है। कम लागत पर मास्क एवं पैड निर्माण कर आय के साथ–साथ इन आवश्यक उत्पादों की कम दामों में सुलभता भी सुनिश्चित होगी।

उन्नति का मार्ग हुआ प्रशस्त

भारत सरकार की उन्नति परियोजना के अंतर्गत राज्य में मनरेगा के तहत आने वाले उन परिवारों को लाभ मिलेगा जिन्होंने मनरेगा में 100 दिन का कार्य पूर्ण किया हो। ऐसे परिवार के एक सदस्य, जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो, को परियोजना के तहत स्किल ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। 30 दिनों की यह ट्रेनिंग रोजगार परक होगी जिससे व्यक्ति जॉब अथवा स्वरोजगार कर आजीविका के साधन प्राप्त कर सके। अधिक से अधिक गरीब परिवारों को लाभान्वित करने के लिए और परियोजना को सफल बनाने के लिए राजीविका भी इस पहल में अहम भूमिका निभा रही है और प्रदेश में इस परियोजना को लागू करने का कार्य राजीविका द्वारा किया जा रहा है।

राजीविका

समूह से समृद्धि तक

ग्रामीण एसएचजी परिवारों के
आर्थिक संबल और आजीविका सृजन
के लिए प्रतिबद्ध

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्